

# असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section I

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं ०. 17]

नई दिल्ली, सोमबार, जावरी 8, 1996/पोष 18, 1917

No. 17]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 8, 1996/PAUSA 18, 1917

## विक्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

### मंकल्प

## नई दिल्ली 8 जनवरी, 1996

पा. म 22/6/95-विकी कर —-दिनांक 2 दिसम्बर, 1995 को हुए वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में अन्तरराज्यीय दिकी के कराधान की समस्या का अध्ययन परने के लिए अधिकारियों और दिगोपत्रों के एक समूह के सकत्य की सिफारिण का संकल्प पारित किया गया था।

2. उत्तत भंकला के अनुसरण में सरकार ने इस प्रयोजन के लिए. एक समृह का गठन करने का निर्णय किया है। एसमें निम्नलिखित णामिल शंगि:—

1.	डा पी. फोम, एन आई.पी.एफ एड पी	ग्रध्यभ
2.	डा. श्रमरीण बागची, एन. पार्ड.पी. एफ., एड पी.	सदस्य
3	डा. पृत्तिन नाथक,योजना श्रायोग	सदस्य
4	वित्त सचिव, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
5.	वित्त समिय, मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
h	विक्तः सन्विवः प्रान्ध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
7-	वित्त सचित्र, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य
Я	वित्त सचिव, श्रसम सरकार	सदस्य
9	बिर्च सचिव, हरियाणा सरकार	गदस्य

- ः इस समह के विचारणीय विषय इस प्रकार होंगे :---
- (क) प्रन्तरराज्यीय विकी के कराधान की समस्या का प्रध्ययन करना और मृत्य विधिन कर लागू करने के माथ-साथ एक मांद्रो बाजार की प्रावश्यकता को महे नजर रखते हुए संभव समाधान का मुझाब देना।
- (श्व) प्रत्य बातों के साथ-साथ तीन विकरपों पर विचार करना प्रश्रित् सी.एस.टी. को एक पूल में केडिट करना जो कि स्वीकृत सूव के श्वाधार पर राज्यां के बीच में बांटा जाएगा, श्रन्तरराज्यीय विश्री की णृत्य रेटिंग और सी.एस.टी. की दर में कटीती।
  - (ग) अन्य संबंधित मामलों के संबंध में सिफारिश करना ।
- 4. यह समूह प्रपंत कार्य के लिए अपनी कार्य विधि तैयार करेगा और अपने प्रध्ययन के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों/संघणाशित क्षेत्रां मे ब्रावश्यक सुचना संगया सकता है।
- 5. अपने कायं को पूर्ण करने के लिए समृह किसी प्रत्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।
- एन.आई.पी.एफ. एड पी ६म समृह तो मिचवालीय महायनाः प्रदान करेगा ।
  - यह समृह 30 जून, 1996 तक श्रपनी रिपोट प्रस्तृत करेगा।
- इ. केरल गुजरात और विहार के बिक्त सिखकों को रिपोर्ट को ब्रस्तिम रूप देने भे पहले विशेष ब्रामिक्ति के रूप में बृखाया जाएगा।

एन एन मुखर्जी, श्रपर सचिव

#### MINISTRY OF FINANCE

## (Department of Revenue)

#### RESOLUTION

New Delhi, the 8th January, 1996

- F. No. 22|6|95-ST.—The Finance Ministers' Conference held on 2nd December, 1995 had adopted a resolution recommending constitution of a group of officials and experts to study the problem of taxation of inter-State sales.
- 2. In pursuance of the resolution Government has decided to constitute a group for this purpose. It will consist of—

1. Dr. P. Shome, NIPF&P	Chairman
2. Dr. Amaresh Bagehl, NIPP&P	Метвег
3. Dr. Pulin Nayak, Planning Commission	Member
4. Finance Secretary, Govt. of Maharashtra	Member
5. Finance Secretary, Govt. of Madhya Prades	h Mcmber
6. Finance Secretary, Govt. of Andhra Pradesi	h Member
7. Finance Secretary, Govt. of West Bengal	Member
8. Finance Secretary, Govt. of Assam	Member
9. Finance Secretary, Govt. of Haryana	Member

- 3. The terms of reference of the group would be-
  - (a) To study the problem of taxation of inter-state sales and suggest possible solution keeping in viewthe introduction of value Added Tax as also the need to create a common market.
  - (b) To consider inter-alia 3 alternatives namely, crediting of CST in a pool to be shared between the States on the basis of an agreed formula, zero rating of inter-State sales and reduction in the rate of CST.
  - (c) To make recommendations regarding other related matters.
- 4. The Group will evolve its own procedures for its work and may for its study call for information as may be necessary from Central and State Governments|Union Territories.
- 5. The Group may co-opt any other expert as a member to facilitate its work.
- 6. The NIPF&P will provide secretarial assistance to the Group.
  - 7. The Group will submit its report by the 30th June, 1996.
- 8. Finance Secretaries of Kerala, Gujarat and Bihar would be invited as special invitees, before finalising the report.

N. N. MOOKERJEE, Addl. Secv.